सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

वर्ष 47 अंक – 19 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 02 – 09 मई 2022 मूल्य पांच रूपए

भ्रष्टाचार को संरक्षण जयराम सरकार की नीयत या नीति पर्यावरण पर विजिलेंस जांच से उठी चर्चा

- कमेटियों का कार्यकाल 12 – 07 – 2021 को समाप्त हो गया था
- इस दौरान सचिव पर्यावरण की जिम्मेदारी पहले के.के.पंथ के पास थी और अब प्रबोध सक्सेना के पास है
- क्या इस दौरान क्लियर किये गये मामले वैध माने जा सकते हैं जबकि कमेटी ही नहीं थी
- सुप्रीम कोर्ट की पर्यावरण पर गंभीरता के बाद मामला हुआ रोचक

शिमला/शैल। प्रदेश विजिलैन्स के पास सरकार के पर्यावरण विभाग को लेकर 11-04-22 को एक शिकायत आयी है। इस शिकायत का संज्ञान लेते हुये विजिलैन्स ने इसमें प्रारंभिक जांच आदेशित करते हुये निदेशक पर्यावरण से आठ बिन्दूओं पर रिकॉर्ड तलब किया है। इसमें जानकारी मांगी गई है कि भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने प्रदेश की एसइएसी का 1-1-2021 से अब तक कब गठन किया गया था या उसको विस्तार दिया था। दूसरा बिंदु है कि केंद्र ने हिमाचल के एसईआईए का 1-1-21 को अब तक कब गठन किया या विस्तार दिया। तीसरा है की 1-1- 21 से अब तक पर्यावरण क्लीयरेंस के कितने मामले आये हैं। चौथा है कि इन कमेटियों की बैठकों में क्या-क्या एजेंडा रहा है। पांचवा है कि इन कमेटियों की कारवायी का विवरण। 1-1- 21 से अब तक प्रदेश की इन कमेटियों द्वारा पर्यावरण के कितने मामले क्लियर किये गये तथा सदस्य सचिव द्वारा उनके आदेश जारी किये गये। कितने मामलों की सूचना डाक द्वारा भेजी गई और कितनों में हाथोंहाथ दी गयी।

विजिलेंस के पत्र से स्पष्ट हो जाता है कि पर्यावरण से जुड़ी इन कमेटियों का महत्व कितना है। किसी भी छोटे बड़े उद्योग की स्थापना के लिए इन कमेटियों की क्लीयरेंस अनिवार्य है। क्योंकि पर्यावरण आज एक गंभीर अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक मामले में यहां तक कह दिया है कि पर्यावरण आपके अधिकारों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। पर्यावरण की इस गंभीरता के कारण ही भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय प्रदेशों के लिए इन कमेटियों का गठन स्वयं करता है। यह अधिकार राज्यों को नहीं दिया गया है। पर्यावरण से जुड़ी क्लीयरेंस के बिना कोई भी उद्योग स्थापित नहीं किया जा सकता है। इसलिए जितने बड़े आकार का उद्योग रहता है उतने ही बड़े उससे जुड़े हित हो जाते हैं और यहीं पर बड़ा खेल हो जाता है। प्रदेश में पर्यावरण विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में नियुक्तियां इसी कारण से अहम हो जाती हैं। इन्हीं को लेकर समय-समय पर संबद्ध अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें आती रही हैं। कसौली कांड इसका सबसे बड़ा प्रमाण रहा है। सरकार अपने विश्वसतों को बचाने के लिए किस हद तक जाती रही है उसका उदाहरण भी यही कसौली कांड बन जाता है। क्योंकि इसमें नामित और चिन्हित लोगों के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो पायी है।

इसी प्ररिपेक्ष में विजिलेंस तक पहुंचे इस मामले में भी अंतिम परिणाम तक पहुंचने को लेकर संशय उभरना शुरू हो गया है। क्योंकि भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गठित यह कमेटी 12-07-2021 को समाप्त हो गई थी। केंद्र को यह सूचना प्रदेश सरकार द्वारा दी जानी थी। ताकि नई कमेटीयों का गठन हो जाता। यह जिम्मेदारी सरकार के सचिव पर्यावरण और संबंधित मंत्री की थी। सचिव की जिम्मेदारी

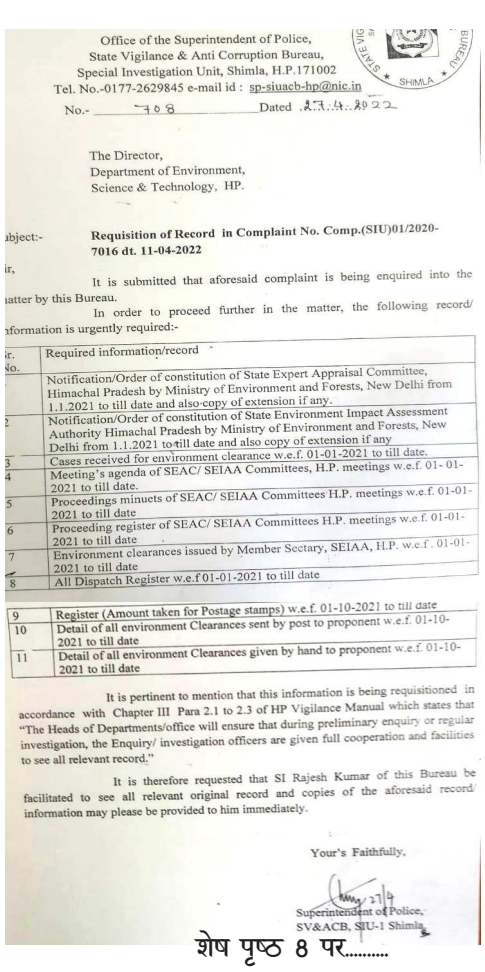

Office of the Superintendent of Police,
State Vigilance & Anti Corruption Bureau,
Special Investigation Unit, Shimla, H.P.171002
Tel. No.-0177-2629845 e-mail id : sp-siuacb-hp@nic.in

No.- 708 Dated 27.4.2022

The Director,
Department of Environment,
Science & Technology, HP.

Subject:- **Requisition of Record in Complaint No. Comp.(SIU)01/2020-7016 dt. 11-04-2022**

Sir,

It is submitted that aforesaid complaint is being enquired into the matter by this Bureau.

In order to proceed further in the matter, the following record/ information is urgently required:-

Sr. No.	Required information/record
1	Notification/Order of constitution of State Expert Appraisal Committee, Himachal Pradesh by Ministry of Environment and Forests, New Delhi from 1.1.2021 to till date and also copy of extension if any.
2	Notification/Order of constitution of State Environment Impact Assessment Authority Himachal Pradesh by Ministry of Environment and Forests, New Delhi from 1.1.2021 to till date and also copy of extension if any
3	Cases received for environment clearance w.e.f. 01-01-2021 to till date.
4	Meeting's agenda of SEAC/ SEIAA Committees, H.P. meetings w.e.f. 01-01-2021 to till date.
5	Proceedings minuets of SEAC/ SEIAA Committees H.P. meetings w.e.f. 01-01-2021 to till date
6	Proceeding register of SEAC/ SEIAA Committees H.P. meetings w.e.f. 01-01-2021 to till date
7	Environment clearances issued by Member Sectary, SEIAA, H.P. w.e.f. 01-01-2021 to till date
8	All Dispatch Register w.e.f 01-01-2021 to till date
9	Register (Amount taken for Postage stamps) w.e.f. 01-10-2021 to till date
10	Detail of all environment Clearances sent by post to proponent w.e.f. 01-10-2021 to till date
11	Detail of all environment Clearances given by hand to proponent w.e.f. 01-10-2021 to till date

It is pertinent to mention that this information is being requisitioned in accordance with Chapter III Para 2.1 to 2.3 of HP Vigilance Manual which states that "The Heads of Departments/office will ensure that during preliminary enquiry or regular investigation, the Enquiry/ investigation officers are given full cooperation and facilities to see all relevant record."

It is therefore requested that SI Rajesh Kumar of this Bureau be facilitated to see all relevant original record and copies of the aforesaid record/ information may please be provided to him immediately.

Your's Faithfully,

Superintendent of Police,
SV&ACB, SIU-1 Shimla

शेष पृष्ठ 8 पर.....

पुलिस भर्ती मामले में पुलिस के खिलाफ पुलिस की जांच कैसे विश्वसनीय होगी

शिमला/शैल। अंततः पुलिस भर्ती रद्द हो गयी है। क्योंकि इसमें परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गया। यह परीक्षा 29 मार्च को हुई थी और रद्द अब मई में हुई जब इसका परिणाम घोषित होने के बाद भर्ती की अगली प्रतिक्रिया भी शुरू हो गयी। स्मरणीय है कि इस पेपर लीक होने की चर्चा मार्च में ही शुरू हो गई थी। उस समय सरकार और पुलिस विभाग ने पेपर लीक होने को सिरे से खारिज कर दिया था। लेकिन यह परीक्षा देने वाले छात्र लगातार पेपर लीक होने का आरोप लगाते रहे। जिसे अन्ततः एस पी कांगड़ा ने अपनी जांच में सही पाया और इसमें चार लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली। आठ लाख में यह पेपर बिकने का आरोप लगा है। सरकार ने इस परीक्षा को रद्द करके इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया। अब जब इसमें जांच बिठा दी गयी है तो इस पर कुछ अधिक कहना जांच को प्रभावित करना बन जायेगा। इसलिये इसमें जांच को लेकर ही कुछ सवाल उठाना आवश्यक हो जाता है।

यह मामला पुलिस भर्ती से जुड़ा है। इस परीक्षा का पूरा संचालन पुलिस विभाग के अपने ही पास था। जिसमें पेपर तैयार करने, परीक्षा करवाने, प्रश्न पत्रों को जांचने आदि का सारा काम पुलिस विभाग के अपने ही पास था। प्रश्न पत्रों की प्रिंटिंग से लेकर परीक्षा केंद्र तक उनको ले जाने का पूरा काम पुलिस के पास था। ऐसे में जब इसमें पेपर लीक हुआ है तो उसमें भी कहीं न कहीं किसी पुलिसवाले की भूमिका अवश्य रही होगी। जिसका अर्थ है कि इसमें आदेशित जांच भी पुलिस के ही खिलाफ है। इसलिये पुलिस के खिलाफ जांच की जिम्मेदारी भी पुलिस को दे दी गयी है। लेकिन जब बहुचर्चित गुड़िया कांड में पुलिस हिरासत में ही मौत हो जाने के मामले की जांच पुलिस को ही दे दी गयी थी तब उसमें यह सवाल उठा था कि पुलिस के खिलाफ पुलिस की ही जांच पर कोई कितना विश्वास कर पायेगा। तब यह जांच पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी गयी थी।

आज उसी तर्ज पर यह सवाल उठा रहा है कि अब भी पुलिस के खिलाफ पुलिस को ही जांच सौंप दी गयी है। इसलिये इस पर भी कोई विश्वास कैसे और क्यों करेगा। प्रदेश में इस तरह की परीक्षाओं में पेपर लीक का यह शायद तीसरा मामला है। पहले के मामलों में भी जाचें बिठायी गयी है। लेकिन उनका परिणाम क्या रहा है यह कोई नही जानता। आज चुनाव की पूर्व सन्ध्या पर घटा यह मामला और इसमें जांच भी पुलिस को ही सौंप देना सरकार की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर जाता है। क्योंकि इस जांच के अदालती परिणाम से पहले अगली भर्ती प्रक्रिया की घोषणा कर दी गयी है।

राज्यपाल ने 'हायर एजुकेशन लीडर-फ्रयूचर ऑफ लर्निंग एण्ड जॉब्स' विषय पर आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता की

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि हमें ग्राम अवधारणा को जीवंत रखते हुए

भावी पीढ़ियों को अपनी सांस्कृतिक परम्पराओं से अवगत करवाना चाहिए ताकि शहरीकरण को कम किया जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उच्च शैक्षणिक संस्थान अपने पाठयक्रम में बदलाव लाकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। राज्यपाल हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षिक संस्थान नियामक आयोग (एचपी-पीईआरसी) द्वारा 'हायर एजुकेशन लीडर-फ्यूचर ऑफ लर्निंग एण्ड जॉब्स' विषय पर आयोजित सम्मेलन में बतौर मुख्यातिथि सम्बोधित कर रहे थे।

राज्यपाल ने कहा कि डिग्री प्राप्त करने के पश्चात विद्यार्थी रोजगार के अवसरों की बात करते हैं तथा रोजगार प्राप्त करना ही उनका मुख्य ध्येय होता है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि क्या हमारा पाठयक्रम एवं विचार विद्यार्थियों को रोजगार के लिए योग्य बना रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप शैक्षणिक संस्थानों में पाठयक्रम तैयार किया जाना चाहिए।

राज्यपाल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में निजी शिक्षण संस्थानों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस दिशा में और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है, जिसके लिए सम्मेलनों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी ज्ञानोपार्जन का दौर है। यह मानवता की व्यापक दृष्टि के साथ मानवीय मूल्यों की स्थापना की सदी है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में उत्कृष्टता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी आदि का समावेश निश्चित रूप से सराहनीय है।

आर्लेकर ने शिक्षक वर्ग से नई शिक्षा नीति का समग्र अध्ययन के उपरांत इसका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि पश्चिम के देशों द्वारा हमें पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझाने का प्रयास करते हैं। परन्तु पर्यावरण हमारी संस्कृति और जीवन शैली का अभिन्न अंग रहा है। उन्होंने कहा कि यदि हम अपनी संस्कृति को समझें सभी प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं नई शिक्षा नीति इन सभी विषयों पर केंद्रित है।

उन्होंने शिक्षा के नए और पुराने पाठयक्रमों तथा स्वास्थ्य शिक्षा में एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी जैसे विषयों के एकीकरण पर विशेष बल दिया।

राज्यपाल ने इस अवसर पर विद्यार्थियों को रोजगार प्रमाण पत्र भी प्रदान किये।

पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी एवं पंजाब जल नियमन और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कर्ण अवतार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि अब तक हो रहा 65 प्रतिशत निर्माण कार्य कार्बन इन्टेसिव है तथा अधिकांश देशों द्वारा इसमें वर्ष 2050 तक 25 प्रतिशत कमी लाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि उपभोक्ता की पसंद सतत् और समावेशी उत्पादों की ओर बढ़ रही है और कॉर्पोरेट रणनीतियों को भी स्थिरता और समावेश पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए, उच्च शिक्षा के लिए रणनीति को कौशल से विशेषताओं में स्थानांतरित कर दिया गया था, उन्होंने कहा और कहा कि हरित अर्थव्यवस्था की नौकरियों में मूल्यों, दृष्टिकोण और क्षमताओं सहित विशेषताओं की आवश्यकता होती है।

इससे पूर्व, हि.प्र. निजी शैक्षणिक संस्थान विनियमन आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल अतुल कौशिक ने राज्यपाल का स्वागत किया और उन्हें सम्मेलन के संबंध में जानकारी दी।

विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति और अन्य प्रबुद्ध व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्यपाल ने मशोबरा स्थित क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र का दौरा किया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शिमला के मशोबरा स्थित क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र

(क्रैगनैनो) का दौरा किया। इस अवसर पर लेडी गर्वनर अनघा आर्लेकर भी साथ थीं।

राज्यपाल ने सेब की 276 किस्मों, नाशपाती की 79 किस्मों और चेरी की 46 किस्मों वाले सबसे बड़े जर्मप्लाज्म केन्द्र पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि प्रयोगशाला से बागीचों तक तकनीक के हस्तांतरण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने सेब की स्थानीय किस्मों को विकसित करने के निर्देश दिए।

आर्लेकर ने केन्द्र में स्थापित सेब के बागीचे का भी दौरा किया। उन्होंने प्रयोगशालाओं का भी निरीक्षण किया और संस्थान के समुचित रखरखाव के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सराहना की। उन्होंने केन्द्र में किए जा रहे अनुसंधान कार्यों की भी सराहना की।

क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र मशोबरा के सह-निदेशक डॉ. दिनेश ठाकुर ने राज्यपाल का स्वागत किया और केंद्र की शैक्षणिक, अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बागवान दैनिक बागवानी कार्यो के लिए केन्द्र की सिफारिशों और अन्य सलाहकार सेवाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। इस अवसर पर वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ.नीना चौहान और अन्य उपस्थित थे।

राज्यपाल ने इससे पहले मशोबरा स्थित नेचर पार्क का भी दौरा किया।

राजभवन में मनाया गया विश्व रेड क्रॉस दिवस

शिमला/शैल। विश्व रेड क्रॉस दिवस के उपलक्ष्य में राजभवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। हिमाचल प्रदेश रेड क्रॉस अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्षा और राष्ट्रीय रेड क्रॉस प्रबन्धन समिति की सदस्य डॉ. साधना ठाकुर, अन्य सदस्य और राज्य

रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारी तथा हि.प्र. रेड क्रॉस अस्पताल कल्याण अनुभाग ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जो हिमाचल प्रदेश राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं, को रेड क्रॉस का झंडा लगाया।

इस वर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस की थीम बी ह्यूमन काइंड है। इस अवसर पर राज्यपाल ने भी रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए अपना अंशदान दिया।

राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आंदोलन को मजबूत करने में युवाओं की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे रोगग्रस्त, विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने जैसी मानवीय गतिविधियों को बढ़ावा देने व संसाधन जुटाने के लिए रेड क्रॉस के प्रति उदारता से दान करें, जो भविष्य में बहुमूल्य जीवन की रक्षा करने में सहायक होगा।

राज्यपाल ने राज्य में रेड क्रॉस आंदोलन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देने पर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, हिमाचल प्रदेश के सभी सदस्यों और स्वयंसेवकों को उनके प्रयासों के लिए बधाई दी।

विश्व रेड क्रॉस दिवस हर वर्ष 8 मई को सर हेनरी डयूनेंट की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्होंने मानव जीवन की रक्षा और मानव पीड़ा को कम करने के लिए वर्ष 1863 में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना और रेड क्रिसेंट आंदोलन की शुरूआत की थी।

इस अवसर पर पोर्टमोर और सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल के विद्यार्थियों ने रेड क्रॉस के संबंध में एक जागरूकता रैली भी निकाली।

राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव संजीव कुमार, रेड क्रॉस सोसायटी के सदस्य एवं रेड क्रॉस अस्पताल कल्याण अनुभाग तथा राजभवन के अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

इसके उपरांत, हिमाचल प्रदेश रेड क्रॉस अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्षा और राष्ट्रीय रेड क्रॉस प्रबंध समिति की सदस्य डॉ. साधना ठाकुर ने विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर रेड क्रॉस भवन, शिमला में सोसायटी द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारम्भ किया।

मुख्यमंत्री ने कांगड़ा में भगवान परशुराम संस्कृति भवन का शिलान्यास किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कांगड़ा जिले के कांगड़ा बाईपास के समीप 5 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले भगवान परशुराम संस्कृति भवन का

शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री ने भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर लोगों को बधाई देते हुए कहा कि भगवान परशुराम ने हमेशा ही कमजोर वर्ग के उत्पीड़न और उनके साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम शास्त्र और शस्त्र दोनों के ज्ञाता थे। उन्होंने कहा कि भगवान शिव ने असहाय और शक्तिहीन की रक्षा के लिए भगवान परशुराम को परशु प्रदान किया था और उसके बाद उनका नामकरण परशुराम हुआ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि हिमाचल से भगवान परशुराम का गहरा नाता है क्योंकि सिरमौर जिले की रेणुका झील भगवान परशुराम की मां माता रेणुका को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि हर वर्ष रेणुका में रेणुका मेला आयोजित किया जाता है जो मां और बेटे के मिलन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ऋषि जमदग्नि के पुत्र भगवान परशुराम, भगवान विष्णु के अवतार थे।

जय राम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को अक्षय तृतीया की भी बधाई देते हुए कहा कि हिन्दू पौराणिक कथाओं के अनुसार अक्षय तृतीया के अवसर पर गंगा नदी स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं और महाभारत का युद्ध संपन्न हुआ था।

मुख्यमंत्री ने इस भवन निर्माण के लिए 21 लाख रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस भवन निर्माण के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने लोगों से इस भवन निर्माण के लिए उदारता से योगदान करने का भी आग्रह किया।

ब्राह्मण कल्याण परिषद की अध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि भगवान परशुराम का भवन देश व प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और परम्परा के संरक्षण ने सहायक सिद्ध होगा।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी, धर्मशाला के विधायक विशाल नैहरिया, देहरा के विधायक होशियार सिंह, वुलफेड के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर, ओबीसी निगम के उपाध्यक्ष ओ.पी. चौधरी, पूर्व विधायक सुरेंद्र काकू, प्रवीन शर्मा, संजय चौधरी, मनोहर धीमान, जिला भाजपा अध्यक्ष चंद्र भूषण नाग, राज्य बास्केट बॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष मुनीष शर्मा और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा

सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज

विधि सलाहकार: ऋचा

अन्य सहयोगी

राजेश ठाकुर

सुदर्शन अवस्थी

प्रदेश में गत चार वर्षों में विद्युत बोर्ड में 4052 पदों पर की गई भर्तियां:जय राम ठाकुर

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि विकास के लाभ जन-जन तक पहुंचाने और

कल्याणकारी नीतियों के कार्यान्वयन में प्रदेश के कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। मुख्यमंत्री सोलन जिला के नालागढ़ उपमंडल के बद्दी में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ के 9वें त्रैवार्षिक साधारण अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। जय राम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में 02 लाख से अधिक कर्मचारी तथा इतनी ही संख्या में पेंशनभोगी हैं। उन्होंने कहा कि 40 हजार से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी भी राज्य में सेवाएं दे रहे हैं। यह सभी पूर्व एवं वर्तमान कर्मचारी प्रदेश को विकास पथ पर अग्रसर करने में सराहनीय भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों की उचित मांगों को पूरा कर रही है और कर्मचारी हित में अनेक ऐसे निर्णय लिए गए हैं, जिन्होंने कर्मचारियों के वर्तमान एवं भविष्य को सुरक्षित किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने अपने सवा चार साल के कार्यकाल में कर्मचारी हित में लिए गए निर्णय अभूतपूर्व हैं और न केवल कर्मचारियों को उनका जायज हक प्रदान किया गया है, अपितु कोविड-19 संकट के बावजूद पूर्ण वेतन, पेंशन और अन्य लाभ सुनिश्चित बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सदैव कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयत्नशील रहेगी।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के विद्युत बोर्ड से सम्बन्धित कर्मचारी विषम परिस्थितियों में भी अपने कार्य को पूर्ण ईमानदारी एवं दक्षता के साथ करते हैं। उन्होंने कहा कि विद्युत बोर्ड के कर्मियों का कार्य कठिन है और राज्य सरकार यह सुनिश्चित बना रही है कि कार्य के दौरान दुर्घटनाओं इत्यादि में कमी लाई जाए। उन्होंने विभाग के तकनीकी कर्मचारियों से आग्रह किया कि कार्य के समय सुरक्षा किट का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देश पर विद्युत बोर्ड द्वारा सभी कर्मियों को सुरक्षा किट प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश विद्युत बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग से हिमाचल पूर्ण रूप से विद्युतिकृत राज्य बना है। वर्तमान राज्य सरकार ने सत्ता संभालते ही विद्युत क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता प्रदान की। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों का शत-प्रतिशत विद्युतिकरण किया गया है। हाल ही में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक नि:शुल्क बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रदेश में 26 लाख विद्युत उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। स्मार्ट सिटी योजना के तहत शिमला व धर्मशाला शहर में 01 लाख 24 हजार स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश विद्युत बोर्ड में विभिन्न पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। गत चार वर्षों में 4052 पदों पर विद्युत बोर्ड में भर्तियां की गई हैं। इनमें से 2721 तकनीकी पदों में की गई हैं। उन्होंने कहा कि विद्युत बोर्ड के तकनीकी वर्ग में गत चार वर्षों में 3069 कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ग के कर्मचारी की समस्याएं सुलझाने के लिए प्रयत्नशील है। प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में राज्य में पहली बार एक समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि पेंशन मामले पर भी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्युत बोर्ड के तकनीकी कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को सुलझाया जाएगा। उन्होंने इस अवसर पर घोषणा की कि प्रदेश विद्युत बोर्ड सब स्टेशन अटेंडेंट के पद पर कार्यरत नॉन आईटीआई कर्मचारियों के लिए पदोन्नति सेवा काल को 10 वर्ष से घटाकर 07 वर्ष किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टीमेट पद से जूनियर शब्द को हटाने के विषय पर विचार-विमर्श के उपरांत निर्णय लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और कर्मचारियों के मध्य समन्वय ही प्रगति का सूचक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों के सहयोग से ही राज्य प्रगति पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कर्मचारियों से आग्रह किया कि सर्वजन हितैषी सरकार को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली

शिमला/शैल। न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में आयोजित एक गरिमापूर्ण समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक भी उपस्थित थे।

इस समारोह का आयोजन राजभवन के दरबार हॉल में हुआ। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने शपथ समारोह की कार्यवाही का संचालन किया और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के संबंध में भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी नियुक्ति वारंट पढ़ा।

राज्यपाल के सचिव विवेक भाटिया ने शपथ पत्र पर राज्यपाल और माननीय न्यायाधीश के हस्ताक्षर प्राप्त किए।

लेडी गवर्नर अनघा आर्लेकर, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति पीएस राणा, जीओसी-इन-सी आरट्रैक लेफ्टिनेंट जनरल एस.एस. महल, महाधिवक्ता अशोक शर्मा, नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौण्डल, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, न्यायालय के अधिकारी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद

शिमला/शैल। राज्य कर एवं आबकारी विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि विभाग को अवैध शराब के खिलाफ की गई कार्यवाही में बड़ी सफलता हाथ लगी है। विभाग ने एक गुप्त सूचना के आधार पर टीम गठित कर जिला शिमला के गांव प्रेमनगर, कोकू नाला गुम्मा में कार्यवाही अमल में लाते हुए 624 बोतल देसी शराब, 48 बोतल अंग्रेजी शराब और 60 बोतल बीयर बरामद की है।

उन्होंने बताया कि जिला शिमला के आबकारी विभाग के उपायुक्त, सहायक आयुक्त एवं अन्य अधिकारियों की टीम ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया। विभाग के पास काफी समय से इस क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री से संबंधित शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इस कार्यवाही में विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई और आबकारी अधिनियम 2011 की धारा 39 के अंतर्गत मुकद्दमा दर्ज किया है। इस संबंध में पुलिस स्टेशन कोटखाई में एफ.आई.आर. दर्ज की है।

उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री व संचालन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए।

मुख्यमंत्री ने बंजार में किए 62 करोड़ रुपये की विकासात्मक योजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कुल्लू जिला के बंजार

विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय प्रवास के दौरान 62 करोड़ रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए। उन्होंने बंजार कला केन्द्र में 57 करोड़ रुपये की लागत की पांच विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए तथा पांच करोड़ रुपये की लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास किए।

मुख्यमंत्री ने नागरिक अस्पताल बंजार की बिस्तर क्षमता बढ़ाने के साथ ही यहां विशेषज्ञ और चिकित्सकों के अतिरिक्त पद सृजित कर भरने की भी घोषणा की। उन्होंने स्वास्थ्य उप-केन्द्र जीभी को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गुशाणी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने, सरूट तथा कांडी में प्राथमिक पाठशालाएं खोलने, राजकीय प्राथमिक पाठशाला रम्बी और शरी को राजकीय माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने, राजकीय माध्यमिक पाठशाला मझली तथा सराची को राजकीय उच्च पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने की भी घोषणा की।

जय राम ठाकुर ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पुजारी में विज्ञान संकाय तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चनोग में वाणिज्य संकाय की कक्षाएं शुरू करने, बछारड में कनिष्ठ अभियन्ता अनुभाग खोलने तथा क्षेत्र के पशु औषधालय को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने की भी घोषणा की।

इससे पूर्व, जय राम ठाकुर ने साई रोपा में 3.29 करोड़ रुपये से निर्मित नेचर पार्क का लोकार्पण किया। उन्होंने बंजार तहसील के पालगी ढलां, रोटे भलां, मुहान गड़सा रैला, धाड़ा, तलाड़ा, रोहन, दोनाल कशाड़ी, धाड़ी, फलाण, कोठी चैणी, खड़ागाड, सेरी, बलगाड़, तांदी चेथर, पेखरी, शराची, लेदा, तिलडु, थाटीबीड़, रतवा इत्यादि के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 25.46 करोड़ रुपये से निर्मित होने वाली जलापूर्ति योजना, ग्राम पंचायत खड़ागाड व सराची में हिदाब सजवाड़, सारथी बांदल के लिए 3.10 करोड़ रुपये से निर्मित होने वाली जलापूर्ति योजना, बंजार शहर के लिए 18 करोड़ रुपये की मल निकासी योजना तथा बंजार में 7.20 करोड़ रुपये से निर्मित होने वाली कृषि उत्पाद विपणन समिति की सब्जी मण्डी का शिलान्यास किया।

राज्य कर एवं आबकारी विभाग की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित

शिमला/शैल। राज्य कर एवं आबकारी विभाग की मासिक समीक्षा बैठक प्रधान सचिव, राज्य कर एवं आबकारी सुभासीष पंडा की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

सुभासीष पंडा ने अधिकारियों को सभी शीर्षों के अंतर्गत लक्ष्यों से बढ़कर राजस्व संग्रह करने के लिए बधाई दी। वित्तीय वर्ष, 2021-22 के लिए कुल राजस्व लक्ष्य 8030 करोड़ रूपये था जिसके विरूद्ध विभाग का राजस्व संग्रह 8494 करोड़ रूपये रहा। यह पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त कुल राजस्व से 20.59 प्रतिशत अधिक है।

प्रधान सचिव ने सभी विभागीय अधिकारियों को ई-वे बिलों की भौतिक सत्यापना के कार्य में तेज़ी लाने तथा वस्तु एवं सेवा कर के अधीन पंजीकृत ईकाइयों के सत्यापन मौके पर जाकर करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि सभी पंजीकृत करदाताओं के जी.एस.टी. रिटर्न नियत तारीख तक ज़मा कराना सुनिश्चित करें। इस कार्य के लिए सभी अधिकारियों को सैक्टर-वार विश्लेषण कर इसे ठीक करने की रणनीति बनाने बारे निर्देशित किया गया ताकि सही व समयबद्ध लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके।

बैठक के दौरान सभी जोनल व ज़िला स्तरीय अधिकारियों को निगरानी दस्तों के माध्यम से एक्साईज प्रवर्तन कार्यवाही अमल में लाने तथा ट्रैक एण्ड ट्रेस मॉडल को धरातल पर लागू करने के निर्देश दिए।

बैठक में आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी यूनुस सहित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

एक नायक बनो और सदैव खुद से कहो मुझे कोई डर नहीं है जैसा मैं सोच सकता हूं वैसा जीवन में जी भी सकता हूँ। .....स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

जब डूबेगी कश्ती तो डूबेगें सारे न तुम ही बचोगे न साथी तुम्हारे

भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का लगातार हनन हो रहा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों की सूची में इस वर्ष 150वें स्थान पर आ गया है। पिछले वर्ष 142 वें स्थान पर था। एक वर्ष में आठ स्थान पर नीचे आ गया है। यह उस समय हो रहा है जब देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार के हाथ में शासन व्यवस्था है संविधान के में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ प्रैस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पिलर माना गया है। संविधान में प्रैस को बाकी तीनों से अलग रखा गया है। इस पर इसमें से किसी का भी सीधा हस्तक्षेप नहीं है। यह इसलिए है ताकि प्रैस समाज के प्रति जवाबदेह हर व्यक्ति से सीधा सवाल कर सके। पूछे हुये सवाल और उसके जवाब तथा उससे जुड़ी जमीनी सच्चाई को पूरी बेबाकी से जनता के सामने रखना प्रैस का कर्म और धर्म दोनों है। प्रैस जनता और शासन व्यवस्था के बीच एक माध्यम एक मीडिया की भूमिका अदा करता है। जब कोई व्यक्ति अदालत तक पहुंचने में भी असमर्थ हो जाता है तब वह अपनी फरियाद लेकर मीडिया के पास आता है ताकि उसकी बात जनता की अदालत तक पहुंच जाये। लोकलाज के चाबुक से शासन और प्रशासन दोनों सजग हो जायें शायद इसलिये जनता को एक बड़ी अदालत की संज्ञा दी गई है। इसी के लिए तो यह कहा गया है **''कि गर तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो''**

लेकिन आज जो हालात हर दिन बनते जा रहे हैं उसमें लोकतंत्र के हर पिलर की भूमिका प्रश्नित्य होती जा रही है। बल्कि कार्यपालिका और व्यवस्था के गठजोड़ के साथ ही इसमें अब न्यायपालिका के भी शामिल होने की चर्चाएं सामने आने लग गयी हैं। यह स्थिति और भी घातक होने जा रही है। क्योंकि जब न्यायपालिका के बीच से ही यह फैसले आने शुरू हो जायें कि अब देश को धर्मनिरपेक्षता छोड़कर धार्मिक देश हो जाना चाहिये तब क्या इसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिये। मेघालय उच्च न्यायालय के जस्टिस सेन के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय से लेकर संसद में सरकार की चुप्पी तक क्या सब कुछ सवालों में नहीं आ जाता है। यदि आज सविधान में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता सरकार और सत्तारूढ़ दल को लग रही है तो उस पर सीधे सार्वजनिक बहस क्यों नहीं उठाई जा सकती। इस बदलाव को एक चुनाव का ही मुद्दा बनाने का साहस सरकार क्यों नहीं दिखा पा रही है। चुनावी मुद्दा बनाकर इस पर जनता का जो भी फैसला आये उसे स्वीकार कर लिया जाये। यह शायद इसलिये नहीं किया जा रहा है कि देश की जनता इसके लिए कतई तैयार नहीं है। क्योंकि जनता ने धर्म का वह रूप भोगा है जहां एक व्यक्ति के छूने मात्र से ही दूसरे का धर्म नष्ट हो जाता था।

लेकिन आज फिर उसी व्यवस्था को लाने की बिसात बिछाई जा रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक वार्षिक अधिवेशन में 22 वर्ष पूर्व तीन संदनीय संसद के गठन का प्रस्ताव पारित कर चुकी है। इस प्रस्ताव पर भाजपा नेता डॉ. स्वामी का फ्रंट लाइन में विस्तृत लेख छप चुका है। जिस पर आज तक किसी ओर से कोई प्रतिक्रिया तक नहीं आयी है क्यों? लेकिन इस पर अमल करने के लिए दूसरे धर्मो को कमजोर और हीन दिखाने के एजेंडा पर अमल शुरू कर दिया गया है। इस पर किसी का ध्यान न जाये इसके लिये आम आदमी को आर्थिक सवालों में उलझा दिया गया है। महंगाई और बेरोजगारी लगातार इसलिये बढ़ रही है क्योंकि आय और रोजगार के सारे साधनों को एक-एक करके प्राइवेट सैक्टर को सौंपा जा रहा है। पवन हंस और एलआईसी इसके ताजा उदाहरण है। आज आर्थिकी और धार्मिकता पर जब भी मीडिया में किसी ने भी कोई सवाल पूछने का साहस किया है तो उस पर देशद्रोह तक के मामले बना दिए गये हैं। कई लोगों की नौकरियां चली गई है। सवाल पूछते वालों के विज्ञापन तक बंद करके और मुकद्दमे बना दिये गये हैं। भाजपा शासित हर राज्य इस नीति पर चल रहा है। हिमाचल की जयराम सरकार तक इन हथकंडो पर आ चुकी है। शैल इसमें भुक्तभोगी है। लेकिन आज यह असहमति मीडिया से चलकर राजनेताओं तक पहुंच गयी है। जिग्नेश मेवाणी प्रकरण इसका ताजा उदाहरण है। पेपर लीक की खबर छापने वाले पत्रकार को एक विधायक के इशारे पर गिरफ्तार करने तक का जब हालात पहुंच जायें तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थितियां कहां तक पहुंच चुकी हैं। अब दर्द का हद से गुजरना दवा होने के मुकाम तक पहुंच चुका है। ऐसे में अब यही कहना शेष है कि

''जब डूबेगी कश्ती तो डूबेगें सारे
न तुम ही बचोगे न साथी तुम्हारे''

प्राचीनतम सांस्कृतिक भूखंडों में से एक है तीरभुक्ति प्रदेश

गौतम चौधरी

आर्यावर्त में तीरभुक्ति (तिरहुत) की अत्यन्त प्राचीन एवं महनीय परम्परा रही है। तथ्यों की मिमांसा से यह ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य प्राय: सप्तसिन्धु प्रदेश तक ही सीमित थे, किन्तु उत्तर वैदिक काल के प्रारम्भ में आर्य की एक शाखा ने सदानीरा (नारायणी) नदी को पार कर तिरहुत क्षेत्र में प्रवेश किया था। लगभग 3000 ई.पू. लिखित शतपथ ब्राह्मण की बहुश्रुत कथा के अनुसार विदेह माथव के नेतृत्व में ऋषिप्रवर पुरोहित गौतम रहुगण के साथ सर्वप्रथम सदानीरा-गण्डकी को पार कर तत्कालीन निर्जन सघन वन प्रदेश में अग्नि स्थापन कर ''यज्ञिय पद्धति'' से इस क्षेत्र को जनावास योग्य बनाया तथा यह क्षेत्र यज्ञिय परम्परा से संयुक्त हुआ।

अग्नि आर्य संस्कृति का प्रतीक माना गया है। तभी से वनाच्छादित यह प्रदेश विदेध अथवा विदेह कहलाने लगा। वसाढ़-वैशाली से प्राप्त गुप्तकालीन मुहर में तथा वृहतर विष्णपुराण में इसे तीरभुक्ति कहा गया जिसका अपभ्रंश तिरहुत है। नदियों पर स्थित होने के कारण ये पूरा क्षेत्र तीरभुक्ति कहलाया। पूर्व मध्यकाल में जिला अथवा परगना को भुक्ति कहते थे। इस प्रकार इस पूरे प्रदेश को तिरहुत के नाम से ही जाना जाता रहा है। विष्णुपुराण एवं भविष्य पुराण के अनुसार अयोध्या के सूर्यवंशी निमि नामक राजा को ऋषि वशिष्ठ के शाप के कारण मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा था। दरअसल, राजा निमि ने एक हजार वर्षो तक चलने वाले यज्ञ कराने का निश्चय किया तथा पुरोहित के लिए वशिष्ठ को आमंत्रित किया, जो सूर्यवंशियों के कुल प्रोहित भी थे। उस समय वाशिष्ठ इन्द्र द्वारा पांच सौ वर्षो तक चलने वाले यज्ञ की बात कहकर स्वर्ग चले गए। यज्ञ समाप्ति के पश्चात पुरोहित बनने का बचन दिया था। धैर्य नहीं रखकर निमि ने गौतम को पुरोहित बनाकर यज्ञ प्रारम्भ किया। इन्द्र के यज्ञ पश्चात ऋषि वशिष्ठ निमि के यज्ञस्थल पर पहुँचे तो गौतम को पुरोहित देख अत्यन्त क्रोधित होते हुए निमि को तत्काल शाप दे दिया। निमि का देहिक जीव नष्ट हो गया। उस वक्त महाराजा निमि का कोई पुत्र नहीं था। यज्ञ अधूरा देख ऋषि प्रवरों ने आपस में विचार-विमर्श कर निमि के अवशेषों को मथकर उस शरीर से जो बालक उत्पन्न किया उसे मिथि कहा जाने लगा। मत्स्य पुराण के अनुसार ''मिथिस्तु मथनाज्जात मिथिला येन निर्मिता।'' दैहिक चेतना से रहित अर्थ की कल्पना कर विदेह शब्द राजा विशेष की वाचकता हो गयी। कालान्तर में विदेह पद राजवंश एवं राज्य दोनों के लिए वाचक हो गयी। व्युत्पत्ति की दृष्टि से मिथि या मिथिला हिमालयी भाषा समूह के शब्द प्रतीत होता है। मिथिला के अन्य व्यवहृत नाम-नेभिकानन, ज्ञानपीठ, स्वर्णागल, शाम्भवी, विकल्मषा, रामानन्दकृति, विश्वभाभिनी, नित्यमंगला, तपोवन, वृहदारण्य आदि है। इन सारे क्षेत्रों को सिद्धपीठ भी कहा जाता है। इस क्षेत्र के सभी निवासी तिरहुतिया कहलाते है। राजा मिथि ने जिस नगर को बसाया उसे मिथिला नाम से जाना गया। मिथिला नगरी सूर्यवंशी राजाओं द्वारा शासित तीरभुक्ति या विदेह की लंबे समय तक राजधानी रही। इसका अर्थ यही है कि तीरभुक्ति नामक प्रदेश की राजधानी मिथिला थी, जिसे राजा मिथि के द्वारा बसाया गया था।

विदेह माथव के उत्तराधिकारियों ने लम्बे समय तक मिथिला में राज्य किया। महाकाव्यों तथा पुराणों में कोई 55 राजाओं का वरण्ण मिलता है, निमि, मिथि, जनक, उदावसु, नन्दिवर्धन, सेकुत, देवरात, वृहद्रय, महावीर, सुधृति, धृष्टकेतु, हर्यश्व, मरु, प्रतीन्धक, कहर्तिरथ, देवमीढ, विवुध, महीद्रक, कहर्तिशत, महारोमा, स्वर्णोमा, हृस्वरोमा, सीरध्वज, कुशध्वज आदि। विदेह के जितने भी राजा हुए सभी तत्वज्ञानी के साथ ब्रह्ममवेत्ता भी थे। मिथि और देवरात के बाद सीरध्वज जनक सबसे अधिक विख्यात हुए, जिनकी सूर्यशाला में शिक्षित थियी के पुत्र अखरानन को मिस्र में सूयोर्पासना की धार्मिक क्रान्ति लाने का श्रेय जाता है।

हल के सीत से प्राप्त धरती पुत्री सीता हुई, जिन्हें जानकी, वैदेही, किशोरी एवं मैथिली भी कहा जाता है। जानकी के अतिरिक्त सरस्वती इसी मिथिलांचल स्थित महोत्तरी-नेपाल के अभृण ऋषि की पुत्री थी। हैमवती, उमा ने महादेव के परिणय सूत्र में आवद्ध होकर जगदीश की पदवी दिलायी।

सति भवतु सुप्रीता देवी शिखर वासिनी।
उग्रेण तपसा लब्धो यथा पशुपति पति:।।

अधिकांश दर्शन के बीज तिरहुत की धरती पर ही अंकुरित हुये। प्राचीन एवं नवीन न्याय के जनक गौतम एवं गंगेशोपाध्याय का आविर्भाव तिरहुत की धरती पर ही हुआ। यही नहीं नवीन न्याय के प्रणेता कहे जाने वाले उदैनाचार्य की जन्मभूमि भी करियन तिरहुत ही है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि यहीं पैदा हुए। तिरहुत का व्यवहार धर्म का दर्पण बन गया - ''धर्मस्य निर्णोज्ञेयो मिथिला व्यवहारत:।'' जैन और बौद्ध धर्मो को तिरहुत में उर्वरा भूमि मिली, परन्तु अन्तिम जनक कराल के दुश्चरित्रता से प्रतापी सूर्यवंश का नाश हो गया और पूरा तिरहुत प्रदेश ''वज्जिगणतंत्र'' के अधीन हो गया। हालांकि, बज्जिगणतंत्र के आठ गणों में से एक विदेह तिरहुत के राजा हुआ करते थे, उनका प्रभाव बरकरार रहा। समय क्रम में वज्जिगणतंत्र का विखराब हुआ और तिरहुत सोलह सौ वर्षो तक परतंत्रता की बेड़ी में जकड़ा रहा। 11वीं शताब्दी में जब कर्णाट क्षत्रीय राजा नान्यदेव इस प्रदेश पर अपना राज्य स्थापित किए तो इसने मिथिला एवं स्वयं को मिथिलेश्वर कहना आरम्भ किया।

लगभग 1600 वर्ष बाद नान्यदेव के आगमन से तिरहुत यानी मिथिला को अपना राजा मिला। कर्णाट शासन काल में विशिष्ट वैवाहिक पद्धति अथवा पंजी व्यवस्था आरम्भ हुई। पांडुलिपियों तथा अभिलेखों को शक-संवत के अनुसार लिपिवद्ध किया जाने लगा। विद्वतजन अपने विद्वता के बलपर धन और मान अर्जन करने लगे। कर्णाट वंश के राजाओं ने वर्ष 1324 तक तिरहुत के संपूर्ण भूभाग पर शासन किया। कर्णाट शासकों की छ: पीढ़ी तिरहुत पर राज्य किया। इसके बाद हरिसिंह देव (1295 से 1324 ई.), जो नान्यदेव के छठे वंशज थे, तुगलतक वंश के संस्थापक और दिल्ली सुल्तान, गयासुद्दीन तुगलक की सेना ने आक्रमण कर दिया। कर्नाट वंश के अंतिम राजा हरिसिंह देव ने अपनी ताकत नहीं दिखाई और किले को छोड़ कर भाग गए।

हरिसिंह देव के पुत्र जगतसिंह देव ने भक्तपुर नायक की विधवा राजकुमारी से विवाह किया और भक्तपुर नामक नगर बसा कर वहां से शासन करने लगे। इधर तिरहुत को गयासुद्दीन तुगलक ने हरिसिंह देव के मंत्री रहे ओनियार वंशी मैथिल ब्राह्मण कामेश्वर ठाकुर को मिथिला (तिरहुत) का शासनाधिकार दे दिया।

कामेश्वर ठाकुर 1354 ई. तक तिरहुत पर शासन किए। इसके बाद ठाकुर के वंशज कई वर्षो तक तिरहुत के कुछ भागों पर शासन करते रहे। उत्तर बिहार के गंधवारिया राजपूत सिमराँव राजाओं के वंशज होने का दावा करते हैं। कर्णट व ओईनवार शासकों की सुव्यवस्था में तिरहुत लंबे समय तक सुरक्षित रहा। वस्तुत: पूरे आर्यावर्त में तिरहुत ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ मुसलमान शासक सबसे अन्त में अपनी प्रभुता स्थापित कर सके। संक्षेप में कहा जा सकता है कि कर्णाटवंशीय काल में एक बार फिर से तीरभुक्ति का एकीकरण हुआ। यह काल कला, साहित्य और तिरहुतिया भाषा, जिसे मैथिली भी कहा जाता है, के विकास का उत्कर्षकाल रहा। मिथिला पर कर्णाटवंशीय का शासन लगभग 200 वर्षो तक चला, जो तिरहुत का स्वर्णाल माना जाता है। उनकी राजधानी नानपुर से सिमरौनगढ़ स्थानान्तरित किया गया, जो कथित रूप से जनक कालीन राजधानी जनकपुर से पश्चिम तथा बारा जिला के कलैया से बीस किलोमीटर दक्षिण-पूंव में अवस्थित है।

कर्णाटवंशीय का वैवाहिक सम्बन्ध काठमांडू उपत्यका के राजा के साथ भी था। गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण के बाद अटूट तिरहुत अप्राकृतिक रूप से दो भागों में विभक्त हो गया। उत्तरी तिरहुत मुसलमान शासक से विमुक्त रहा जबकि दक्षिण तिरहुत, मुसलमान शासक के अधीनस्थ हो गया। बाद में चलकर मुसलमान शासक ओइनवार वंश को दक्षिण मिथिला का राज्य सौंप दिया, जिसके एवज में निर्धारित कर लेता रहा। उत्तरी मिथिला का बचा हुआ शेष भाग का विभाजन पुन: हुआ, जिसे हम सुगौली सन्धि के नाम से जानते हैं। एकल तिरहुत के विभक्त होने के बाद ही समय-समय पर सीमा का विवाद उचरता रहा है।

नेपाल का नामकरण का कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलता है। कहा जाता है कि नेत्र मुनी बागमती एवं विष्णुमती के तट पर टेकु नामक स्थान पर अपने घर में तपस्या किया करते थे। वहाँ के संरक्षक राजा ने उन्हीं के नाम से उक्त स्थल का नाम रख दिया। तिब्बती भाषा में ''ने'' का अर्थ घर और पाल का अर्थ ऊन होता है। अर्थात ऊन का घर। संस्कृत वांगमय के अनुसार देवताओं के वासस्थान को ने कहा जाता है। भाषाविदों ने लिखा है -ने नीति: ताम्पालवति नेपाल:। इसे और स्पष्ट करते हुए लिखा गया है कि न्याय: पाल्यते य: स: नेपाल:। बाद में चलकर यह पूरा क्षेत्र नेपाल के नाम से जनप्रिय हो गया। वृहद विष्णु पुराण, मिथिला माहात्म्य वर्णित तथ्यों के आधार पर कोसी से गंडक तक, गंगा प्रवाह से हिमालय वन तक की भूमि को तीरभुक्ति अथवा मिथिला कहा गया है। महेन्द्र नारायण शर्मा कृत मिथिलादेशीय- पञ्चांग तिरहुत का वर्णन इस प्रकार है -

गंगा वहथि जनिक दक्षिण पूर्व कौशिकी धारा।
पश्चिम वहथि गण्डकी उत्तर हिमवत वन विस्तारा।
कमला त्रियुगा अमृता धेमुरा वागमती कृत सारा।
मध्य वहथि लक्ष्मणा प्रभृत्ति से मिथिला विद्यागारा।।

आज ये लगभग पाँच हजार वर्ष पूंव यह क्षेत्र गंगासागर का भाग था और अरब सागर से भी जुड़ा था। अजातशत्रु के समय तिरहुत का ऐसा उत्कर्ष काल था कि चीन के दक्षिण भाग की वस्तियों का नाम मिथिला नगरी के नाम पर रख दिया गया। यथा मानचाड का नाम मिथिला रखा गया था। तिरहुत का अतीत कहता है कि यह धरती याचना नहीं करता परन्तु अयाची ने शंकर को जन्म देकर संपूर्ण जगत को धन्य का दिया। भामती ने दीप को सहेज कर वाचस्पति का अंक पूरा किया, भारती अर्धांगिनी के रूप में मंडन मिश्र को विजयश्री दिलायी, विद्योत्तमा ज्ञान दात्री बना कालिदास का, सीता ने सहिष्णुता दी समस्त नारी समाज को।

आयुष विभाग में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के 200 पद भरने का निर्णय

शिमला। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आयुष विभाग में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के 200 पद भरने का निर्णय लिया गया। इनमें से 100 पद सीधी भर्ती के माध्यम से और शेष 100 पद बैचवार आधार पर भरे जाएंगे।

बैठक में आयुष विभाग में अनुबंध आधार पर आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के 100 पद भरने का भी निर्णय लिया गया। इन 100 पदों में से 52 पद सीधी भर्ती के माध्यम से और शेष 48 पदों को बैचवार आधार पर भरा जाएगा।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के खुंडियां में नया विकास खण्ड कार्यालय खोलने और इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 14 पद सृजित कर उन्हें भरने का निर्णय लिया। इस विकास खण्ड के अधीन 20 पंचायतें होंगी।

मंत्रिमंडल ने पंचायती राज विभाग के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 32 पदों को भरने का निर्णय लिया।

बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के छह पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

राज्य के प्रत्येक जिले में ग्रामीण विकास कार्यालय के परियोजना निदेशक के कार्यालय को सुदृढ़ करने के लिए ग्रामीण विकास में विभिन्न श्रेणियों के 25 पदों को भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए आवश्यक पदों के सृजन के साथ मण्डी जिले के धर्मपुर में श्रम मण्डल कार्यालय एवं उप रोजगार कार्यालय खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने उद्यमियों को उद्योग अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए राज्य की बड़ी औद्योगिक इकाइयों को विद्युत शुल्क में रियायत देने का निर्णय लिया है।

मंत्रिमण्डल ने अनुबंध पर नियुक्त व्यक्ति, दिहाड़ी श्रमिक/कंटींजेंट वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने और अंशकालिक कामगारों की सेवाओं को दिहाड़ीदार में बदलने के लिए मौजूदा कट ऑफ तिथि 31.03.2022 और 30.09.2022 को तय करने के लिए अपनी कार्योत्तर मंजूरी दी।

बैठक में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए कांगड़ा जिले की उप तहसील सुलह में पटवार वृत्त वोडा का पुनर्गठन करते हुए नया पटवार वृत्त सिहोटू बनाने का निर्णय लिया गया।

बैठक में सोलन जिले के कंडाघाट, धर्मपुर और कुठाड़ के प्रारंभिक शिक्षा खण्डों से निकालकर नया खण्ड शिक्षा कार्यालय खोलने का भी निर्णय लिया गया। इसके

सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन के साथ उन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने शिक्षा खण्ड औट के गांव रैहन में नया प्राथमिक विद्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में सिरमौर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर भरापुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इस केंद्र के प्रबंधन के लिए विभिन्न श्रेणियों के पांच पदों के सृजन और भरने को भी मंजूरी प्रदान की गई।

बैठक में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए लाहौल-स्पीति जिला के केमो में स्वास्थ्य उप केंद्र और बिलासपुर जिला के जबालियां में स्वास्थ्य उप केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने सिरमौर जिले में पशु औषधालय चाड़ना को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की गई। अस्पताल के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजन के साथ उन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की। इससे क्षेत्र की पांच से अधिक पंचायतों के लोगों को लाभ होगा।

बैठक में कुल्लू जिला के हरिपुर पशु औषधालय को तीन पदों के सृजन के साथ पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। इससे क्षेत्र की आठ पंचायतों को लाभ होगा।

बैठक में सिरमौर जिला की नाहन विधानसभा क्षेत्र के देवका पुडल्ला, कियारी और संभालका गांवों में आवश्यक पदों के सृजन के साथ पशु औषधालय खोलने का भी निर्णय लिया गया।

बैठक में शिमला जिला में पशु औषधालय पुलवाहल को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया। अस्पताल के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजन व इन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। इससे क्षेत्र की तीन से अधिक पंचायतों के लोगों को सुविधा प्राप्त होगी।

मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के केओलीधार एवं सहज, कुल्लू जिला के गांव कराड़सू में नये आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। प्रत्येक आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र में विभिन्न श्रेणियों के तीन-तीन पदों के सृजन के साथ उन्हें भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में प्रदेश में हिमाचली लोक संगीत और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लता मंगेशकर स्मृति पुरस्कार आरम्भ करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने चम्बा जिले के चुवाड़ी में नया लोक निर्माण विभाग का मण्डल खोलने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग में शास्त्री शिक्षकों को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (संस्कृत) के रूप में नामित करने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में क्षेत्र की छात्राओं की सुविधा के लिए मण्डी जिला के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भंगरोटू में विज्ञान की कक्षाएं आरम्भ करने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने जिला सिरमौर के राजकीय उच्च पाठशाला बोहोलियन, नेहरस्वर, टोक्यां, जगला-भूद और बड़थल मधाना और कुल्लू जिला की राजकीय उच्च पाठशाला मलाणा को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला और सिरमौर जिले के राजकीय माध्यमिक पाठशाला, देवका, नालका, कोडेवाला, पन्याली और सत्तार भदोन को राजकीय उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। नव स्तरोन्नत पाठशालाओं के सुचारू प्रबंधन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 56 पदों के सृजन और भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने मण्डी जिला के राजकीय उच्च पाठशाला खौली को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, राजकीय माध्यमिक पाठशाला चुलाथाच व योरना और कुल्लू जिला के राजकीय माध्यमिक पाठशाला पिपलेज और सरसारी को राजकीय उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा राजकीय प्राथमिक पाठशाला बिहार और सुजैणी को माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने के साथ विभिन्न श्रेणियों के 27 पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने जिला सिरमौर के नौहराधार में नया राजकीय स्नातक महाविद्यालय खोलने के साथ-साथ इसमें संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 18 पद सृजित कर भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने हाल ही में खोले गए सरदार पटेल विश्वविद्यालय मण्डी और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के क्षेत्राधिकार के निर्धारण को अपनी स्वीकृति प्रदान की। मंडी, कांगड़ा, चंबा, लाहौल-स्पीति और कुल्लू जिले के 137 महाविद्यालय सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के अन्तर्गत, जबकि शिमला, सिरमौर, सोलन, किन्नौर, बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना जिलों के 165 महाविद्यालय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के अंतर्गत आएंगे।

मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुलेहड़ा और धबीड़ी में विज्ञान की कक्षाएं और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोहारली में वाणिज्य कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया ताकि इन क्षेत्रों के छात्रों की सुविधा हो सके।

मंत्रिमंडल ने गौ अभ्यारण्य/गौसदनों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को प्रति गाय प्रति माह 500 रुपये से बढ़ाकर 700 रुपये करने का निर्णय लिया।

प्रकाश बादल की तस्वीरों को नेशनल जियोग्रोफिक में मिला स्थान

वर्ल्ड वंडरफुल फोटोग्राफी ने दिया ब्रोंज अवार्ड

शिमला। हिमाचल प्रदेश से सम्बन्ध रखने वाले वाईल्डलाईफ

फोटोग्राफर प्रकाश बादल की तस्वीरों ने बुलंदियों के ऐ और पायदान को पार किया है । इस बार प्रकाश की तस्वीर को मशहूर मंच नेशनल जियोग्राफिक ने स्थान दिया है। प्रकाश द्वारा खींची गयी स्पाईडर हंटर पक्षी की एक तस्वीर को नेशनल जियोग्राफिक ने सराहते हुए अपनी गैलरी में स्थान दिया है। नेशनल जियोग्राफिक के सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को प्राथमिकता के साथ दर्शाया गया है और हज़ारों लोग इसकी प्रशंसा कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त हाल ही में 'वर्ल्ड वंडरफुल फोटोग्राफी' संस्था द्वारा देश विदेश से हज़ारों फोटोग्राफरों में से ब्रोंज मैडल से पुरस्कृत किया है। इस प्रतियोगिता में देश विदेश के हज़ारों फोटोग्राफरों के चित्रों में से प्रकाश के चित्रों ने ब्रोंज हासिल करने का गौरव प्राप्त किया है। प्रकाश के चित्रों को इससे पहले भी अनेक सम्मान मिल चुके हैं। उनकी तस्वीरों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खूब सराहा गया है। मीडिया के अनेक वरिष्ठ पत्रकारों ने भी अपनी सोशल मीडिया वाल पर प्रकाश के चित्रों को स्थान देकर उन्हें खूब प्रोत्साहित किया है। प्रकाश बादल पिछले कई वर्षो से पक्षियों की दुर्लभ तस्वीरों को खींचने के लिए भारत के चप्पे चप्पे में घूमते रहते हैं। उन्होंने पिछले चार वर्षो में अनेक पुरस्कार एवं उपलब्धियां हासिल की हैं। उनके पक्षियों के प्रति अद्भुत लगाव को देखते हुए हिमाचल के निवर्तमान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उनकी वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी से प्रभावित होते हुए प्रकाश की खूब प्रशंसा करते हुए उन्हें एक पत्र भी लिखा है। इसके अतिरिक्त उनकी तस्वीरों की प्रशंसा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रामनाईक, उत्तराखंड वन विभाग, तथा स्ट्रेबो पिक्सल क्लब द्वारा भी उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश वन विभाग में कार्यरत प्रकाश शौकिया तौर पर पक्षियों की तस्वीरें उतारते हैं और अपने निजी संसाधनों से देश भर के पक्षियों की तस्वीरें उतारने के लिए देश के अनेक जंगलों में घुमते रहते हैं । अब तक उन्होंने देश भर के लग भाग 400 विभिन्न पक्षियों की तस्वीरें उतार ली हैं और उनका यह सफर अभी तक जारी है।

युवा शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने एवं रोज़गारपरक शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध

शिमला। प्रदेश सरकार राज्य में गुणात्मक और रोज़गारपरक शिक्षा प्रदान कर युवाओं को स्वावलम्बन की राह पर अग्रसर कर रही है। हिमाचल सरकार प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दे रही है। प्रदेश सरकार ने तकनीकी शिक्षा संस्थानों में कई नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए हैं।

वर्तमान में तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कुल 363 तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान क्रियाशील हैं। प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में 5 इंजीनियरिंग कालेज, 4 फार्मेसी कॉलेज, 16 बहुतकनीकी संस्थान, 138 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं एक मोटर ड्राइविंग एवं हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी ऑपरेटर स्कूल तथा निजी क्षेत्र में 9 इंजीनियरिंग कालेज, 16 फार्मेसी कालेज, 9 बहुतकनीकी संस्थान, 14 डी-फार्मेसी कालेज एवं 151 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत हैं। इन संस्थानों की अन्तर्ग्रहण क्षमता 58439 है।

प्रदेश सरकार ने जिला कांगड़ा के राजकीय महिला बहुतकनीकी संस्थान रैहन में कम्प्यूटर इंजीनियरिंग और सिविल इजीनयरिंग डिप्लोमा पाठयक्रम शुरू किया है। प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में अगले शैक्षणिक सत्र से जवाहर लाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर में कम्प्यूटर सांइस में बीटेक तथा सिविल इंजीनियरिंग में एमटेक कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। राजकीय महिला बहुतकनीकी संस्थान कण्डाघाट में इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा राजकीय बहुतकनीकी संस्थान तलवाड़ में फार्मेसी डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा।

प्रदेश में कुशल मानव संसाधन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जिला बिलासपुर के बंदला में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज और शिमला जिला के कोटला ज्यूरी में महात्मा गांधी इजीनियरिंग कॉलेज अनुमोदित किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने मण्डी जिला के करसोग और सिराज, कांगड़ा जिला के जन्दौर एवं सुलह तथा कुल्लू के दलाश में बहुतकनीकी संस्थान स्थापित करने के लिए अधिसूचना जारी की है।

प्रदेश सरकार ने कांगड़ा जिला के सुलह विधानसभा क्षेत्र में राजकीय फार्मेसी महाविद्यालय खोलने के लिए अधिसूचना जारी की है। शिमला जिला के अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय अभियान्त्रिकी महाविद्यालय प्रगतिनगर में डिग्री स्तर का इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग व्यवसाय (ट्रेड) वर्ष 2019 से चलाया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने प्लम्बिग, वेल्डिंग, इलैक्ट्रिकल मरम्मत जैसी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए 'कौशल आपके द्वार' योजना आरम्भ की है। इस योजना के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को न्यूनतम सम्भावित दरों पर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने शिमला शहर में 63.06 करोड़ रुपये लागत की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ने लिफ्ट के समीप 10.50 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित आजीविका भवन का लोकार्पण किया। इस भवन में 217 दुकानें, 12 बेकरी और दो लिफ्ट सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं।

जय राम ठाकुर ने शिमला स्मार्ट सिटी के तहत 33 करोड़ रुपये की लागत से रिज के स्थिरीकरण और खुली जगह के विकास कार्य, ऑकलैंड टनल शिमला के समीप 6.49 करोड़ रुपये की लागत से 200 वाहनों की पार्किंग क्षमता वाली पार्किंग के निर्माण कार्य तथा एसडीए कॉम्पलैक्स कसुम्पटी में 6.21 करोड़ रुपये की लागत से 150 वाहन क्षमता की पार्किंग के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने श्री गुरूद्वारा साहिब शिमला के समीप 6.86 करोड़ रुपये की लागत से स्थानीय बस अड्डे के विकास कार्य का शिलान्यास भी किया। यहां 250 वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा शिमला शहर में नागरिकों और यहां भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए शिमला स्मार्ट सिटी के तहत विभिन्न विकासात्मक परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं पर लगभग 760 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सुव्यवस्थित निर्माण और विभिन्न सुविधाओं के उपलब्ध होने से शिमला शहर का बहुआयामी विकास सुनिश्चित होगा।

उन्होंने कहा कि शिमला शहर में 120.30 करोड़ रुपये की लागत की 22 पार्किंग परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। यह निर्माण कार्य पूर्ण होने पर लगभग 2,800 वाहनों के लिए अतिरिक्त पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी। इनमें आईजीएमसी के नए ब्लॉक और आईजीएमसी ऑडिटोरियम के सामने पार्किंग, विकासनगर, संकटमोचन, एसडीए कॉम्पलेक्स और टुटू बंगला कॉलोनी में पार्किंग का निर्माण प्रमुख रूप से शामिल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर में 95 करोड़ रुपये की लागत से 12 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण और सुधारीकरण कार्य किया जा रहा है। इससे कार्ट रोड एरिया में ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि शिमला शहर में 17 किलोमीटर पैदल पथ व फुटपाथ का निर्माण किया जा रहा है, जिससे शहर में पैदल चलने में लोगों को सुविधा उपलब्ध होने के साथ-साथ उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। इस पर 73 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हिमऊर्जा द्वारा सरकारी भवनों पर सोलर पावर प्लांट ग्रिड स्थापित की जाएगी, इससे बिजली की बचत होगी। इस कार्य पर 9 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहर में ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए 25 करोड़ रुपये व्यय कर 20 नई ई-बसें खरीदने की प्रक्रिया जारी है तथा शीघ्र ही तारादेवी में 3 करोड़ रुपये की लागत से ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत शिमला और धर्मशाला में 65 करोड़ रुपये की लागत से एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की जाएगी। इस सेंटर के माध्यम से नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं की 24 घंटे निगरानी के साथ-साथ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस विभाग को शहर में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने और यातायात उपकरणों की खरीद के लिए 4 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला शहर में लोगों की आर्थिकी को बढ़ावा देने के लिए व्यावसायिक और निजी क्षेत्रों की 106 करोड़ रुपये लागत की 22 परियोजनाओं को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। इनमें बुक कैफेज, वेंडिंग जोन और राम बाजार, लोअर बाजार, सब्जी मंडी आदि की दुकानों का नवीनीकरण कार्य शामिल हैं। शिमला शहर में 12 पार्कों और खुले स्थानों को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लाया गया है। इस पर 12 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। शिमला शहर में 11 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम और शिक्षा निदेशालय में स्मार्ट स्टूडियो विकसित किए जाएंगे। इसके लिए 7 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि स्मार्ट सिटी के अलावा शिमला शहर में केंद्र प्रायोजित अमृत मिशन के तहत 238 करोड़ रुपये लागत की 47 परियोजनाओं में से 37 परियोजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इन परियोजनाओं पर 172 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में शिमला शहर अभूतपूर्व विकास का गवाह बना है। शिमला शहर में व्यवस्थित विकास और विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए नवोन्मेष प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में 80 करोड़ रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने सिरमौर जिले के हरिपुरधार में तीन दिवसीय मां भंगयाणी मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरिपुरधार को नागरिक अस्पताल, पशु औषधालय भरोग-भनेड़ी को पशु अस्पताल, स्वास्थ्य उप-केंद्र तारे को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सैल, जार गराबी और थाना करोड़ को राजकीय उच्च विद्यालय, राजकीय उच्च विद्यालय देवड़ी खराहन और चैरस को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में स्तरोन्नत करने की घोषणा की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सैल में पटवार वृत्त खोलने और हरिपुरधार मेला मैदान में मंच के लिए 15 लाख रुपये की राशि प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नायब तहसीलदार नोराधार सप्ताह के दो दिन बोघधार में बैठेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सिरमौर के हाटी समुदाय ने अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखा है, जो वास्तव में प्रशंसनीय है।

जय राम ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से बिखरी हुई पार्टी है और कांग्रेस नेताओं को एकजुट करने के लिए हिमाचल जैसे छोटे राज्य में चार कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने सिरमौर जिले के श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के लिए हरिपुरधार में लगभग 80 करोड़ रुपये की 22 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए।

मुख्यमंत्री ने 3.70 करोड़ रुपये की लागत से पक्की की गई जामू कोटी के सम्पर्क सड़क, 2.81 करोड़ रुपये की लागत से पक्की की गई रनफूआ से जगरोग सड़क, 2.69 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित खारकोब उंगर कांडो सड़क, 2.08 करोड़ रुपये की लागत से पक्की की गई पुलीलाणी भलोट भालोना से संगड़ाह सम्पर्क सड़क, 7.94 करोड़ रुपये की लागत से पक्की की गई खाला क्यार बांदल सुराख सड़क, 7.33 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित लगणू गांव तक मगवा सूंई सड़क, संगड़ाह में 9.77 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित तीस बिस्तरों की क्षमता वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन, संगड़ाह में 10.25 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित राजकीय महाविद्यायल के आवासीय भवन, ग्राम पंचायत रजाना के धार पल्यारा बरनू के लिए 45 लाख रुपये की लागत से निर्मित ग्रेविटी जलापूर्ति योजना, तहसील संगड़ाह की ग्राम पंचायत आंधेरी में 42 लाख रुपये की लागत वाली उठाऊ जलापूर्ति योजना मन्दोल और बदवाना के संवर्धन कार्य, जल जीवन मिशन के तहत तहसील संगड़ाह की ग्रांम पंचायत भावल में 37 लाख रुपये की ग्रेविटी जलापूर्ति योजना जोगी का बाग, ज्यार, लोधिया और अरावाला में पुरानी तथा क्षतिग्रस्त जी.आई. पाइप को बदलने के कार्य तथा विद्युत मण्डल राजगढ़ के तहत पणोग में 5.77 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 33/11 केवी सब-स्टेशन का लोकार्पण किया।

जय राम ठाकुर ने 8.59 करोड़ रुपये लागत से नौहरा से चूड़धार सम्पर्क सड़क के निर्माण कार्य, 4.49 करोड़ रुपये लागत से निर्मित होने वाली गेहल से डमैना बारवा दासाकणा सम्पर्क सड़क के कार्य, 4.23 करोड़ रुपये से निर्मित होने वाली रामपुर से पलाहू वाया कनहारी लाणाचेता सड़क के कार्य, हरीपुरधार में 84 लाख रुपये लागत से निर्मित होने वाले सहायक अभियन्ता द्धए.ई.त्र कार्यालय एवं आवास, हरीपुरधार में 1.56 करोड़ रुपये लागत से निर्मित होने वाले उप-तहसील कार्यालय/आवास के निर्माण कार्य, 56 लाख रुपये की लागत से विकसित की जा रही शिव मूर्ति के निकट पार्क के निर्माण कार्य और पार्क के ट्रैकर हॉस्टल से ट्रैक रूट एवं कैफेटेरिया, नई राहें, नई मंजिलें योजना के अन्तर्गत 1.49 करोड़ रुपये लागत के चूड़धार के विकास के लिए विभिन्न कार्यो, ददाहू में 27 लाख रुपये की लागत से सार्वजनिक नल की स्थापना के साथ रियल टाइम जल गुणवत्ता निगरानी प्रणाली, जल शक्ति वृत्त नाहन के अन्तर्गत 3 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं में पेयजल की गुणवत्ता तथा मात्र की निगरानी के लिए आई.ओ.टी. आधाारित इनस्ट्रूमेंटेशन तथा तहसील ददाहू की ग्राम पंचायत बिरला में 30 लाख रुपये की उठाऊ जलापूर्ति योजना करोंदवाला का शिलान्यास किया।

ग्रेटर परवाणू औद्योगिक क्षेत्र को किया जाएगा विकसितः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार परवाणू क्षेत्र में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए ग्रेटर परवाणू औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने की योजना बना रही है। यह जानकारी मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने सोलन जिला के परवाणू में परवाणू इंडस्ट्रलिस्टस एसोसिएशन (पीआईए) सदन का लोकार्पण करने के उपरान्त दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को देश का औद्योगिक हब बनाने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में उद्यमियों को अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए हर संभव प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि परवाणू राज्य का प्रवेश द्वार होने के साथ-साथ हिमाचल का सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र भी है। उद्यमियों को और अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को बेहतर करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि पीआईए ने समाज कल्याण कार्यो में भी प्रशंसनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन प्रत्येक वर्ष मानव सेवा के लिए लगभग एक हजार यूनिट रक्त एकत्रित करता है।

स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए।

पीआईए के अध्यक्ष सुनील तनेजा ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए एसोसिएशन की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी।

सांसद सुरेश कश्यप, दून के विधायक परमजीत सिंह पम्मी, नालागढ़ के पूर्व विधायक के.एल. ठाकुर और एसोसिएशन के सदस्य भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

पुलिस कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को निःशुल्क परिवहन सुविधा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए शीघ्र आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की सुविधा के लिए उन्हें हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क परिवहन सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने के लिए जारी किया गया अपना प्रवेश पत्र ही दिखाना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में कांस्टेबल पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा रद्द कर दी थी।

मुख्यमंत्री ने परवाणू में 218 करोड़ रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने सोलन जिला के कसौली विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत परवाणू में लगभग 218 करोड़ रुपये लागत की 20 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए।

मुख्यमंत्री ने परवाणू में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कसौली विधानसभा क्षेत्र के धर्मपुर में जल शक्ति मंडल खोलने, गड़खल में 20 बिस्तरों की क्षमता वाले उपमंडल आयुर्वेदिक अस्पताल, गम्बरपुल (हरिपुर) में पशु औषधालय, भोजनगर में पशु औषधालय तथा परवाणू में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लोगों की सुविधा के लिए 50 बिस्तरों वाले अस्पताल धर्मपुर में तीन चिकित्सक, दो पैरा मेडिकल स्टाफ और छह नर्स के पद सृजित किए जाएंगे। साथ ही ईएसआई अस्पताल परवाणू में चिकित्सकों के 06 पद सृजित किए जाएंगे।

जय राम ठाकुर ने कोटिनाम्भ सेरी (नेरीकलां), रान, मेहलन गांवों में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की घोषणा की। उन्होंने पटाबरावरी तथा तिरडो में पटवार वृत्त तथा जाबल जमरोट में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की घोषणा की।

उन्होंने राजकीय उच्च विद्यालय रौड़ी तथा राजकीय उच्च विद्यालय गनोल को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। उन्होंने राजकीय माध्यमिक विद्यालय करोल, नेरीकलां, दतियार, गुनाई, चामत भड़ेच को राजकीय उच्च विद्यालयों में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। उन्होंने कसौली विधानसभा क्षेत्र के पांच राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में वाणिज्य संकाय की कक्षाएं आरम्भ करने तथा दो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान संकाय की कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्राथा में अटल आदर्श स्कूल भी स्थापित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने पुलिस चौकी भोजनगर को स्थायी करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि गांव के लोगों की सुविधा के लिए गांव क्यारड़ को पटवार वृत्त धर्मपुर में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कसौली विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की दो मुद्रिका बसें संचालित की जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने इससे पहले परवाणू के सेक्टर-2 के गेब्रियल सड़क में 75 लाख रुपये की लागत सेस निर्मित पीआईए सदन, बरोटीवाला मंधाला-परवाणू सड़क मार्ग के 11.30 करोड़ रुपये के चौड़ीकरण व उन्नयन कार्य तथा लोहांजी में 4.30 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित प्री-फेब्रिकेटिड क्षेत्रीय कुष्ठ अस्पताल का लोकार्पण किया। उन्होंने परवाणू में ईएसआई अस्पताल के लिए 55 लाख रुपये की लागत से निर्मित ऑक्सीजन संयंत्र, तहसील सोलन की ग्राम पंचायत नेरीकलां और इसके साथ लगते गांवों के लिए 1.27 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित उठाऊ जलापूर्ति योजना स्योथ-कमलोग के संवर्द्धन कार्य तथा बड़ोग में 48 लाख रुपये की लागत से निर्मित 'इन्सपेक्शन हट' के अतिरिक्त आवास का लोकार्पण किया।

उन्होंने धर्मपुर में सहायक राज्य आबकारी एवं कराधान कार्यालय के लिए 56 लाख रुपये से निर्मित कार्यालय भवन एवं टाइप-2 क्वार्टर तथा तहसील कसौली में पुलिस चौकी गड़खल में 84 लाख रुपये की लागत से निर्मित टाइप-2 क्वार्टर और 21.70 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होटल न्यू रोस कॉमन कसौली का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर शालाघाट-अर्की-कुनिहार-बरोटीवाला सड़क पर गंभर खड्ड पर 5.18 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित डबललेन फुटपाथयुक्त आर्क पुल, भोजनगर से चक्की का मोड़ सड़क पर कौशल्या खड्ड पर 2.80 करोड़ रुपये की लागत वाले पुल, परवाणू-खड़ीन-बनासर-भोजनगर सड़क पर कमली खड्ड पर 6 करोड़ रुपये लागत से फुटपाथयुक्त डबललेन पुल, पुलिस थाना धार्मपुर के लिए 90 लाख रुपये लागत से निर्मित होने वाले टाईप-3 आवास, 17.50 करोड़ रुपये की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धर्मपुर में 50 बिस्तर क्षमता वाले अतिरिक्त खण्ड, 104.03 करोड़ रुपये की लागत से कसौली विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों के लिए गिरी नदी से उठाऊ पेयजल योजना, 37.03 करोड़ रुपये की लागत से उठाऊ जलापूर्ति योजना सातियां शिवा, उठाऊ जलापूर्ति योजना गड़खल लड़ाह, उठाऊ जलापूर्ति योजना सुनाड़ी-आंजी, उठाऊ जलापूर्ति योजना गोरथी, उठाऊ जलापूर्ति योजना सेरी थाना, ग्रेविटी जलापूर्ति योजना कसौली, ग्रेविटी जलापूर्ति योजना जगेशु, ग्रेविटी जलापूर्ति योजना झंगेड़, उठाऊ जलापूर्ति योजना हुड़ंग कोटला, उठाऊ जलापूर्ति योजना भावगुड़ी, 90 लाख रुपये की लागत से उठाऊ जलापूर्ति योजना उप-मोहाल नरयाला और उप-मोहाल चंदरैणी, 91 लाख रुपये की लागत से उठाऊ जलापूर्ति योजना तरोल और कियारवा सिहारदी के रिमॉडलिंग कार्य का शिलान्यास किया।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने अपने गृह क्षेत्र में स्वागत करते हुए कहा कि कसौली निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न गांवों के लिए गिरी नदी से 104.03 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली जलापूर्ति योजना, जिसका मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया वह क्षेत्र की पानी की समस्या को हल करने में मील पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि कसौली में उपमण्डलाधिकारी कार्यालय भी मुख्यमंत्री की उदारता के कारण ही संभव हुआ है।

अनुराग ठाकुर ने माजरा में हॉकी एस्ट्रोटर्फ की आधारशिला रखी

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के लोगों में खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने की स्वाभाविक प्रतिभा है और भारत सरकार इसका उपयोग करने के

लिए हर सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय युवा मामले और खेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में माजरा स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में हॉकी एस्ट्रोटर्फ की आधारशिला रखने के बाद यह बात कही।

इस हॉकी मैदान पर करीब 6 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें कन्या छात्रावास, चेंज रूम, शौचालय, कोचिंग आदि जैसी सुविधाएं होंगी। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य सरकार द्वारा राज्य में खेल के विभिन्न पर्वों में नवोदित खिलाड़ियों को पहचानने के लिए प्रतिभा खोज कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। मंत्री ने कहा कि गतका, कलारीपयड़ु, थांग-टा, मल्लखंबा और योगासन नाम के पांच पारंपरिक खेल आगामी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का हिस्सा होंगे और भारत सरकार उन्हें वैश्विक मंच पर लोकप्रिय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री ने कहा कि पारंपरिक खेलों को भी राज्य में मान्यता दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि पांवटा साहिब में इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा।

इस साल बेंगलुरु में हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में दो राष्ट्रीय रिकॉर्ड और यूनिवर्सिटी गेम्स के 76 पिछले रिकॉर्ड टूट गए, जो हमारे युवाओं में प्रतिभा को दर्शाती हैं, युवा मामले और खेल मंत्री ने कहा।

उन्होंने जिला रेडक्रास सोसायटी की ओर से शिलाई तहसील के ग्राम कोटा से मौजूद दिव्यांग कुलदीप सिंह को स्कूटी भेंट की।

मुख्यमंत्री ने छतरी में 14.09 करोड़ रुपये की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने सराज विधानसभा क्षेत्र की उप-तहसील छतरी में 14.09 करोड़ रुपये लागत की विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए, इसमें ग्राम पंचायत गतू और छतरी में 13.04 करोड़ रुपये की 6 परियोजनाओं के लोकार्पण और 1.05 करोड़ रुपये की 2 परियोजनाओं के शिलान्यास शामिल है।

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर मेला मैदान चपलांदी में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए छतरी में महाविद्यालय खोलने, माध्यमिक पाठशाला वोहल सैंज को उच्च पाठशाला, माध्यमिक पाठशाला बगड़ाथाच को उच्च पाठशाला, प्राथमिक पाठशाला गतू गलू को माध्यमिक पाठशाला, प्राथमिक पाठशाला रूमणी को माध्यमिक पाठशाला में स्तरोनत करने और वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिहणी में विज्ञान कक्षाएं आरम्भ करने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत जरेहड़ व ग्राम पंचायत गतू के बेठवां में स्वास्थ्य उप-केंद्र खोलने, थुनाची के स्वास्थ्य उप-केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने, काकड़ाधार में पशु औषधालय खोलने, मैहरीधार में वन निरीक्षण कुटीर का निर्माण करने तथा चपलांदी में नई राहें-नई मंजिल के अन्तर्गत निरीक्षण कुटीर का निर्माण करने की भी घोषणा की।

उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत काकड़ाधार में 80 लाख रुपये की सेरी बागा जलापूर्ति योजना के पुनर्निर्माण से गांव नेहरा, कान्ढल, भझौणी तथा गांव चावग के लोगों को पर्याप्त पेयजलापूर्ति की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत छतरी में 79 लाख रुपये की बेठवां बहाव सिंचाई योजना तथा 1.97 करोड़ रुपये की छतरी से कोहीधार बहाव सिंचाई योजना के लोकार्पण और 67 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाली जलापूर्ति योजना ब्रयोगी, गिनी निहरी तथा करगानू बगडैहन से पर्याप्त जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध होगी। कृषि उत्पादों की पैदावार में बढ़ोत्तरी होने से क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी।

उन्होंने कहा कि 3.07 करोड़ रुपये की लागत से राणा बाग से बिहानी सेरी सड़क तथा 4.91 करोड़ रुपये की लागत से छतरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का लोकार्पण होने से क्षेत्र के लोगों की मांग पूरी हुई है। उन्होंने 38 लाख रुपये की लागत से बनने वाले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चपलांदीधार के भवन का भी शिलान्यास किया गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने 1.50 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित छतरी विश्राम गृह के अतिरिक्त भवन का भी लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि ग्राम पंचायत बगड़ाथाच, झरेड़, गतू तथा ग्राम पंचायत छतरी में 1896 लाख की विभिन्न पेयजल योजनाओं तथा ग्राम पंचायत बरयोगी, काकड़ाधार, छतरी और बुंग रैल चौक में 1629 लाख की पेयजल योजनाओं का 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।

मुख्यमंत्री ने कौशल रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के जागरूकता वाहन कौशल रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य में तकनीकी व्यवसायिक और शैक्षिक प्रशिक्षण को मजबूत करने के प्रयासों के लिए कौशल विकास निगम की सराहना की। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा राज्य के युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण के साथ गुणवत्तापूर्ण कौशल बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निगम द्वारा प्रदेश में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के तहत उन्नत कौशल संस्थानों का विकास किया गया है। इनमें 7 ग्रामीण आजीविका केंद्र, 5 शहरी आजीविका केंद्र, 10 मॉडल करियर केंद्र, एक महिला पॉलिटेक्निक, एक उत्कृष्टता केंद्र और एक आईटीआई शामिल है। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा राज्य में लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रेजुएट ऐड-ऑन, बैचलर ऑफ वेकेशन तथा रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

कौशल रथ के माध्यम से प्रदेश भर में युवाओं को निगम द्वारा चलाये जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों की जानकारी प्रदान की जाएगी।

इस अवसर पर विधायक विनोद कुमार, बलबीर वर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुभाशीष पंडा, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी, कौशल विकास निगम की प्रबंध निदेशक कुमुद सिंह, महाप्रबंधक सुनील ठाकुर व हर्ष अमरिंदर सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाषः 0177-2805015, 94180-15015 फैक्सः 2805015

रस्मी समारोहों से बाहर निकलकर प्रतिभा सिंह कैसे जयराम सरकार को घेरती है इस पर लगी निगाहें

- कांग्रेस को भाजपा और आप दोनों से एक साथ लड़ना होगा
- कांग्रेसी चुनावों में ही आपसी स्कोर सेटल कर लेते हैं इस धारणा से बाहर निकलना होगी चुनौती

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस इकाई के पुनर्गठन में जिस तरह से हाईकमान ने हर नेता को उचित मान सम्मान देते हुये गठन में संतुलन का परिचय दिया है उसका पूरे प्रदेश में स्वागत हुआ है। कांग्रेस कार्य कर्ताओं के साथ ही आम आदमी में भी एक उम्मीद जगी है। इसका परिचय शिमला की सफल रैली से मिल जाता है। रैली में सामूहिक नेतृत्व का व्यवहारिक प्रदर्शन और उसके माध्यम से पूरी पार्टी को जो एकजुटता संदेश दिया गया है वह सब भी प्रशंसनीय रहा है। लेकिन क्या इतने मात्र से ही कांग्रेस भाजपा और आप से मुकाबला करते हुये सता पर काबिज हो पायेगी। यह सही है कि भाजपा के किसी भी आंतरिक सर्वे में पार्टी का प्रदर्शन दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंचा है। इस सर्वे के परिणामों से भाजपा इतना हिल गई है इसका पता भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप के उस ब्यान से लग जाता है जिसमें उन्होंने आप प्रभारी सतेंद्र जैन पर टिकट आवंटन के लिये पैसे मांगने का आरोप लगाया है। लेकिन यह भी सच है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं/ नेताओं का पार्टी छोड़कर जाना रुका नहीं है। अभी भी लोग आप में शामिल हो रहे हैं। कांगड़ा में सुधीर शर्मा, जगजीवन पाल और गोमा को लेकर चल रही चर्चाओं का दौर अभी तक भी थमा नहीं है। भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुये सुरेश चंदेल अभी भी पार्टी की मुख्यधारा के नेता नही बन पाये हैं। भाजपा अभी भी आप के साथ ही मुद्दे ज्वाइन करने की रणनीति पर चल रही है। कांग्रेस को लेकर यह धारणा अभी तक बनी हुई है कि इसके नेता चुनावों में ही एक दूसरे के साथ स्कोर सेटल कर लेते हैं। क्योंकि पुराना अनुभव ऐसा ही रहा है और इसके नेता सार्वजनिक रूप से इस आश्य के एक दूसरे पर आरोप भी लगाते रहे हैं। आज कांग्रेस को इस पृष्ठभूमि और धारणा से व्यावहारिक रूप से बाहर निकलना होगा। लेकिन क्या कांग्रेस इस दिशा में क्रियात्मक कदम उठा पा रही है यह सवाल अब उठने लग पडा है। क्योंकि अभी तक कांग्रेस जयराम सरकार के खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा खड़ा नहीं कर पायी है। जो आरोप पत्र लाने की कवायद एक समय की गयी थी वह अब पृष्टभूमि में चली गयी है। यह तय है कि जब तक सरकार को गंभीर मुद्दों पर जनता में नहीं घेरा जायेगा तब तक कांग्रेस कुछ बड़ा नहीं कर पायेगी। कांग्रेस का यह पक्ष अब तक कमजोर चल रहा है। और इसका कोई कारण भी अब तक सामने नहीं आ पाया है। नयी टीम ने जितने भी नेताओं को जिम्मेदारियां दी गयी है वह लगभग सभी चुनावों में अपने-अपने क्षेत्रों में व्यस्त हो जायेंगे और दूसरे स्थानों पर समय नहीं दे पायेंगे। आज जनता जिस महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है उसके लिये इस सरकार की कौन सी नीतियां कैसे जिम्मेदार है यह जनता को पूरे प्रमाणों के साथ समझाने की आवश्यकता है। अन्यथा इन मुद्दों को भी परिस्थितियों का ही प्रतिफल कहकर इनकी धार को भी कुन्द करने का प्रयास किया जायेगा। यह सही है कि आज प्रतिभा सिंह को प्रदेश का अध्यक्ष बनाना समय की आवश्यकता थी। क्योंकि पूरी टीम में वही एक ऐसा नेता है जो पूरे प्रदेश में समय दे पायेंगी। वही स्व. वीरभद्र सिंह की राजनीतिक विरासत का इस समय लाभ लेने की स्थिति में है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि उन्हें अपने में वीरभद्र सिंह बनने के लिए समय लगेगा। इसलिए प्रतिभा सिंह सरकार को मुद्दो पर कैसे घेर पाती है यह देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि इस दिशा में अभी तक कुछ भी ठोस सामने नही आया है। अभी तक जयराम के प्रशासन को भी बांधकर रखने की दिशा में कांग्रेस का कोई बड़ा कदम सामने नहीं आया है। बल्कि यह खतरा बराबर बना हुआ है कि जिस आप के पास केजरीवाल की दो सफल रैलियों के बावजूद अभी तक प्रदेश का ऐसा कोई आदमी नहीं जुड़ पाया है जो भाजपा कांग्रेस को बराबर घेर सके। लेकिन आने वाले दिनों में यदि आप में ऐसा कोई शामिल हो जाता है जो भाजपा और कांग्रेस दोनों से एक साथ तीखे सवाल पूछने शुरू कर देता है तब कांग्रेस को भी बचाव की मुद्रा आना पड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस भी लंबे वक्त तक प्रदेश की सता पर काबिज रही है। 2014 से अब तक इसी कांग्रेस को भाजपा ने सत्ता से बाहर रखा है। इन व्यवहारिक पक्षों को सामने रखते हुये यह बड़ा सवाल बन जाता है कि प्रतिभा सिंह इस दिशा में क्या और कैसे कदम उठाती हैं। प्रदेश की जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जो उम्मीद बंधी है उसे कैसे सफल बनाती हैं।

खालिस्तानी झण्डा प्रकरण पर बहुत कमजोर है मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया

शिमला/शैल। प्रदेश के धर्मशाला स्थित विधानसभा परिसर पर कोई रात के अंधेरे में खालिस्तान का झण्डा लगाकर खालिस्तान के समर्थन

के बारे में भी लिख जाता है। पुलिस किसी को भी घटनास्थल पर पकड़ नहीं पायी है। बाद में अज्ञात लोगों पर सरकारी संपत्ति को विकृत करने के अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लेती है। इस प्रकरण में मुख्यमंत्री के उनके ट्वीट के माध्यम से आई प्रक्रियाओं में कहा गया है कि यह परिसर केवल शीतकालीन सत्र के दौरान ही उपयोग में आता है इसलिये वहां पर सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी नहीं रहती है। इसी का लाभ उठाकर रात के अंधेरे में उस काम को अंजाम दिया गया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि साहस हो तो दिन के उजाले में ऐसा करके दिखायें। स्वभाविक है कि मुख्यमंत्री ने यह जानकारी मिलते ही प्रशासन से इस का पूरा ब्यौरा लिया होगा और उसके आधार पर यह प्रतिक्रिया जारी की होगी। मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया से पहला सवाल यह उठता है कि जो संपत्तिया रेगुलर उपयोग में नहीं हैं उनकी सुरक्षा के प्रति सरकार ज्यादा सजग नहीं है। क्या मुख्यमंत्री की यह प्रतिक्रिया स्वीकार्य हो सकती है? विधानसभा परिसर एक ऐसा स्थल है जहां पर सीसीटीवी कैमरे और कुछ सुरक्षाकर्मी हर समय तैनात रहना अनिवार्य है। भले ही उनकी संख्या कम हो। खालिस्तान का झण्डा और नारा परिसर के मुख्य द्वार पर लगा मिला है। ऐसे में यह सब करने वालों के चित्र कैमरे में भी अंकित होना और उनका सुरक्षाकर्मी की नजर में आना स्वभाविक हो जाता है। लेकिन यह विवरण सामने नहीं आया। भले ही दर्ज मामले में देशद्रोह की धारा भी जोड़ दी गयी है लेकिन इस पर स्थिति स्पष्ट होना आवश्यक है क्योंकि इस घटना से एक सप्ताह पहले ही शिमला में एंटी टेरेरिस्ट फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने एक पत्रकार वार्ता करके खालिस्तानीयों को चुनौती दी थी। जिसके बाद गुप्त चर एजेंसियों का और स्तर्क होना आवश्यक हो जाता है। इस परिपेक्ष में अब तक सरकार के पास कोई ठोस जानकारी न होना पूरे प्रशासन पर सवाल उठाता है। क्योंकि अब जो सीमायें सील करने के कदम उठाये गये हैं वह सब तो शांडिल्य के ब्यान के बाद ही उठा लिये जाने चाहिये थे। प्रदेश का हर आदमी इस घटना की निंदा करने के साथ ही सरकार से सवाल भी पूछेगा। क्योंकि प्रदेश की सुरक्षा की दिन-रात की जिम्मेदारी सरकार की है। ऐसे में रात के अंधेरे में विधानसभा परिसर के मुख्य द्वार पर यह घट जाये और मुख्यमंत्री इस तरह की प्रतिक्रिया दे तो उससे आम आदमी के मनोबल और सरकार पर उसके विश्वास तथा निर्भरता सभी पर एक साथ प्रभाव पड़ेगा। सरकार को इस पर सारी जानकारियां प्रदेश की जनता से सांझी करनी चाहिए। क्योंकि खालिस्तानी तत्व 2021 से ही इस संबंध में धमकीयां देते आ रहे हैं। इस संदर्भ में कोई भी देरी सारे घटनाक्रम को राजनीतिक आईने में देखने के लिये आम आदमी को मजबूर कर देगी जो कि और भी घातक होगा।

भ्रष्टाचार को संरक्षण

...पृष्ठ 1 का शेष

पहले के.के. पंथ के पास रही है और अब प्रबोध सक्सेना के पास है। मंत्री स्तर पर पर्यावरण विभाग स्वयं मुख्यमंत्री के पास है। 12-07-2021 को समाप्त हो चुकी कमेटियों का गठन क्यों नहीं किया गया? क्या इस दौरान प्रदेश में किसी नए उद्योग का प्रस्ताव ही नहीं आया। सरकार ने 2019 की अपनी उद्योग नीति में भी संशोधन किया है। क्या इस संशोधन के दौरान भी इन कमेटियों का कोई जिक्र नहीं आया। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो सरकार की नीयत और नीति पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अब जब किसी ने विजिलेंस के पास यह शिकायत कर दी है तो इसी दौरान भारत सरकार ने भी प्रदेश से इसमें जवाब तलब किया है। लेकिन यह चर्चा भी सामने आ रही है कि भारत सरकार में भी इस मामले को रफा-दफा करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। संबद्ध अधिकारी अपनी गलती मान कर भारत सरकार से क्षमा कर दिये जाने की गुहार लगा रहे हैं। राजनीतिक स्तर पर भी प्रयास किये जा रहे हैं। जिस तरह की गंभीरता सुप्रीम कोर्ट पर्यावरण को लेकर दिखा चुका है उसके परिदृश्य में इस पर गंभीर कारवाई बनती है। क्योंकि इस दौरान जितने भी उद्योगों के मामले मामलों में पर्यावरण क्लीयरेंस जारी किये गये होंगे उनकी कानूनी वैधता संदिग्ध हो जाती है। क्योंकि जिसने भी यह क्लीयरेंस अनुमोदित की होगी वह उसके लिए अधिकृत ही नहीं था। चुनावी वर्ष में यह मामला सरकार की सेहत पर कितना असर डालता है और विपक्ष की इसी पर क्या प्रतिक्रिया रहती है यह देखना दिलचस्प होगा।